

प्रपक

डा० एम० सी० जोशी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादून दिनांक: 12 जनवरी, 2005

विषय:- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 853/1/2004-06(1)/23/03, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष रु० 4,63,07,100/- (रु० चार करोड़ तिरप्पन लाख सत्त हजार एक सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2004 में लेखाशोधक के पैरा 17-के स्थान पर अब निम्नवत् पैरा एवं जान की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

17- 'स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तु वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशोधक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारपण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य उपक्रमों में निवेश-आयोजनागत-00-04-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर० ई० सी० से ऋण-10-04 से स्थानान्तरित)-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा'।

उक्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के असायकीय संख्या 2293/क/वि० अनु०-3/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

/

(डा० एम० सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 2^{री} /12004-06(1)/23/03 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल ।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री का मा० मंत्र्यमंत्रों जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन का मा० राज्य मंत्रों के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 7- सचिव, निरंतरण विभाग।
- 8- विल अनुभाग-3
- 9- प्रभारी एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(डा० एन०सी० जोशी)

अपर सचिव

